आकाशवानी
क्षेत्रीय समाचार एकांश
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शनिवार 05.07.2025
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- उत्तराखंड को कैंपा योजना के लिए केंद्र की सौ फीसदी मंजूरी, 439 करोड़ रुपये से विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार।
- मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी जिलाधिकारियों को जन समस्याओं के निस्तारण के लिये आवश्यक निर्देश दिये।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जिले के लिये साढे पांच सौ करोड़ रुपये की 107 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
- और, देहरादून में आयोजित नागरिक उड्डयन सम्मेलन में देश–विदेश की 117 कंपनियों ने हवाई सेवाओं के विस्तार और सुरक्षा को लेकर विचार विमर्श किया।

कैंपा फंड–शत प्रतिशत स्वीकृति

उत्तराखंड को वर्ष 2025–26 के लिए प्रस्तावित 439 दशमलव पांच करोड़ रुपये की कैंपा कार्य योजना को भारत सरकार की ओर से शत–प्रतिशत मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस स्वीकृति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री का आभार व्यक्त किया।

नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैम्पा की कार्यकारी समिति की बैठक में उत्तराखंड के सभी अवशेष प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। समिति ने राज्य की योजनाओं को मानकों के अनुरूप पाया और सभी अपेक्षित विवरण स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किए गए। यह पहला अवसर है जब उत्तराखंड की संपूर्ण वार्षिक योजना को पूरी तरह मंजूरी मिली है।

प्रमुख वन संरक्षक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. समीर सिन्हा ने बताया कि यह मंजूरी समय से मिलने के कारण राज्य में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जा सकेगी। इससे पहले मई 2025 में केंद्र सरकार ने प्रथम चरण में 235 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की थी, जिसकी पहली किश्त राज्य सरकार ने वन विभाग को जारी कर दी है।

वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कैम्पा टीम को बधाई दी और अपेक्षा जताई कि वन विभाग इस राशि का उपयोग निर्धारित समय और मानकों के अनुसार राज्य हित में करेगा।

वीडियो कांफ्रेसिंग समीक्षा

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने देहरादून से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलाधिकारियों से जनसमस्याओं की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्युत, पेयजल और अन्य नागरिक सेवाओं से

जुड़े विभाग अपने कार्यक्षेत्रों का नियमित निरीक्षण करें और टेढ़े खंभों, लटकी तारों व टूटी पेयजल पाइपलाइनों की मरम्मत जल्द कराएं।

फील्ड विजिट पर विशेष जोर देते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जब तक अधिकारियों स्वयं मौके पर जाकर स्थिति का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं करेंगे, तब तक वे आम जनता की वास्तविक समस्याओं को समझ नहीं पाएंगे।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की जिलावार समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना में तेजी लाई जाए। जिन केंद्रों में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, वहां उपकरणों की शीघ्र व्यवस्था करते हुए उन्हें सक्रिय किया जाए।

सम्मान

देहरादून के आईआरडीटी ऑडिटोरियम में 'स्वास्थ्य संवाद एवं चिकित्सा सेवा सम्मान समारोह 2025' का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यभर के 26 उत्कृष्ट चिकित्सकों को सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म और टेलीमेडिसिन जैसी पहलों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भौगोलिक चुनौतियों से भरे उत्तराखंड जैसे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म, ई–हॉस्पिटल मैनेजमेंट, और टेलीमेडिसिन जैसी पहलों की अत्यधिक आवश्यकता है और इसके क्रियान्वयन में डॉक्टरों की भागीदारी अहम है।

कार्यक्रम में निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. आशुतोष सयाना ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा और व्यवहार में संतुलन जरूरी है और सम्मानित हुए डॉक्टर युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा हैं।

मोबिलिटी प्लान

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में देहरादून शहर के मोबिलिटी प्लान की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को सुधार कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन 10 स्थानों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, वहां एक माह के भीतर काम शुरू किया जाए, जबकि शेष कार्यों की डीपीआर 31 जुलाई तक पूरी कर ली जाए। जिलाधिकारी को सभी कार्यों की नियमित निगरानी के निर्देश भी दिए गए।

मुख्य सचिव ने हाल ही में चौड़ी की गई सड़कों पर नो पार्किंग जोन में वाहनों के खड़े होने पर चिंता जताते हुए सख्त प्रवर्तन की बात कही। उन्होंने कहा कि नए पार्किंग स्थलों की तलाश जारी रखी जाए और कमर्शियल भवनों की पार्किंग का शत–प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाए। सचिवालय, पवेलियन ग्राउंड और परेड ग्राउंड के नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग की संभावनाओं पर विचार करने के निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने आढ़त बाजार को शिफ्ट करने की प्रक्रिया में देरी पर नाराजगी जताई और संबंधित कार्यों की समय–सीमा तय कर शीघ्र रिपोर्ट देने को कहा।

श्री बर्धन ने देहरादून की अगले 25 से 30 वर्षों की ट्रैफिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक योजना तैयार करने की आवश्यकता पर भी बल दिया और जल्द ही इस पर बैठक बुलाने को कहा।

'विकास संकल्प पर्व'

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में आयोजित 'विकास संकल्प पर्व' में 550 करोड़ रुपये की 107 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने हरिद्वार जिले के चहुंमुखी विकास के लिए 13 नई घोषणाएं भी कीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से हरिद्वार जिले में आधारभूत सुविधाओं को मजबूती मिलेगी और विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने विभिन्न विभागों की योजनाओं के तहत लाभार्थियों को लगभग 76 लाख रुपये के चेक और पीएम आवास योजना के तहत आवास की चाबी भी सौंपी।

श्री धामी ने कहा कि हरिद्वार में रोपवे, हेलीपोर्ट, पॉड टैक्सी, और कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है ताकि इसे विश्वस्तरीय नगरी के रूप में विकसित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2027 का कुंभ और कांवड़ यात्रा ऐतिहासिक, दिव्य और सुरक्षित हों, इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जाएंगी।

सम्मेलन

देहरादून में आयोजित ''नागरिक उड्डयन पर मंत्रियों के सम्मेलन'' में देश और दुनिया से आई 117 विभिन्न कंपनियों, संस्थानों और राज्यों के अधिकारियों के बीच नागरिक उड्डयन क्षेत्र को लेकर व्यापक विचार–विमर्श हुआ। सम्मेलन में राज्यों और कंपनियों ने आपसी सहयोग से उड्डयन सेवाओं के विस्तार और सुधार पर सहमति जताई।

बैठक में हेलीपोर्ट्स के विस्तार, हेलीकॉप्टर सेवाओं के बेहतर उपयोग और हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने पर विशेष जोर दिया गया। हाल में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए हवाई सुरक्षा को और मजबूत करने की आवश्यकता पर चर्चा हुई। कंपनियों ने राज्यों से उड़ान सेवाओं के विस्तार के लिए नीति और सब्सिडी प्रदान करने की मांग भी की।

सत्र के दौरान सड़कविहीन क्षेत्रों में हेली और ड्रोन सेवाओं के जरिए आपदा प्रबंधन और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई।

सम्मेलन में एयर इंडिया, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फिक्की, मैकेंजी, रिलायंस, भारत टूरिज्म समेत कई निजी और सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

यूपीएस

केंद्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली–एनपीएस के अन्तर्गत वर्तमान में उपलब्ध सभी कर लाभ नई शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना–यूपीएस में भी लागू रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीएस को कर ढांचे के अन्तर्गत शामिल करना पारदर्शी, सुगम और कर–कुशल विकल्पों के माध्यम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति सुरक्षा को मजबूत करने के सरकार के प्रयास में एक और कदम है।

समाचार पत्रों की सुर्खियों

हिमालयी राज्यों के लिये अलग विमानन नीति की खबरो को सभी समाचार पत्रो ने प्रमुखता दी हैं। हिन्दुस्तान समाचार पत्र लिखता हैं– मुख्यमंत्री धामी ने नागर विमानन सम्मेलन –2025 में उठाया मुददा, हिमालयी राज्यों के लिये अलग विमानन नीति बने।

चारधाम यात्रा के लिये अगले चरण में सितंबर से प्रारंभ होने वाली हेली सेवाओं का संचालन नये मानको के साथ होगा, दैनिक जागरण की खबर हैं।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुडी एक खबर पर अमर उजाला का शीर्षक हैं– जरूरत पडी तो हेलीकाप्टर से पंहुचायी जायेगी पोलिंग पार्टिया, राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी डीएम से मांगा चुनाव संबधित प्लान।

पांच साल बाद शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा, नवोदय टाइम्स की सुर्खी है। समाचार पत्र के अनुसार इस बार यह यात्रा टनकपुर से शुरू होकर चंपावत, पिथौरागढ, धारचूला से गूंजी होते हुये मानसरोवर तक का रास्ता तय करेगी।